

प्रेषक,

रुणाप कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 17/जनवरी/2009

विषय:-मै0 भारत आयल एवं वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0 को ग्राम मुकिमपुर परगना मंगलौर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार में उद्योग की स्थापना हेतु कुल 0.995 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-451/भूमि व्यवस्था-भूकय-8 दिनांक-14.06.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 भारत आयल एवं वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0 को ग्राम मुकिमपुर परगना मंगलौर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार में उद्योग की स्थापना हेतु कुल 0.995 है0 भूमि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत गाटा संख्या-72/2,74/6 74/7 के अनुसार कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधारी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दस वर्ष की अवधि के अन्दर, जिराकी मणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिराको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना) के लिये करेगा जिराके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिराके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिरा प्रयोजनार्थ कय किया गया था।

उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तारण करता है तो ऐसा अन्तारण उक्त अधिनियम के परोक्षता हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उससे भूस्वामी अनुरूपित जाति/जनजाति के न हों और अनुरूपित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उससे भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शारानादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- कय की जाने वाली भूमि का भू- उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित करके शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु सामान्य सुविधाओं के लिए भवन निर्माण का प्लान राक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्मार्ट जॉनिंग क्षेत्र के लिए निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

9- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग Integrated hazards and Electronics Waste Management Facility इकाई की स्थापना हेतु किया जायेगा। प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा।

10- प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11- प्रश्नगत इकाई में पूंजी निवेश/निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अभिशमन विभाग से नियमानुसार अनापत्ति/सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

12- इकाई को प्रस्तावित भूमि में उक्त परियोजना स्थापित करने पर भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

13- किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

14- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15- सम्बन्धित इकाई से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायगी।

16- सम्बन्धित इकाई को भू-उपयोग करने से पूर्ण राक्षस एंजेन्सरी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी, तभी इकाई द्वारा भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु किया जा सकेगा।

17- उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन, हानि की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिस शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ०प०सं०- 1601 /संमदिनांकित/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश के उद्योग विभाग से सम्बन्धित समस्त विन्दुओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 3- सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, मद्रास गण्डल, पौड़ी

3

- 5- निदेशक, उद्योग, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
- 6- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2-न्यूक्लियर रोड, सिन्धुखुल, देहरादून।
- 7- निदेशक गैर भारत आयात एवं निर्यात नियंत्रण वि० की० 5 जी०एफ ईस्ट आफ कैलाश नई दिल्ली।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, राखिवालय।
- 9- प्रभाषी भीडिया केन्द्र, राखिवालय।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रन्ताग बहोनी)
अनुसंधान।